All-Inclusive Current Affairs for Prelims 2023

Polity Class-11

THE WIRE | SUPPORT

POLITICS | ECONOMY | EXTERNAL AFFAIRS

Nobody Can Be Forced to Take the COVID-19 Vaccine: Supreme Court

A bench of Justices L. Nageswara Rao and B.R. Gavai said bodily autonomy and integrity are protected under Article 21 of the Constitution.

The Wire Staff
May 02, 2022

Bodily Autonomy

- ➢ इसका अर्थ है अपने शरीर पर स्वयं का अधिकार
- ➢ यह अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है
  (अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण)
- ➢ उदाहरण : टीका न लगवाने का अधिकार, सुरक्षित गर्भपात का अधिकार

- ❑ सरकार लोगों को टीका लगवाने के लिए मजबूर कर सकती है? **नहीं**
- ❑ सरकार टीका न लगवाने वाले लोगो पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है ? **हाँ**

नोट: जनहित में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यदि ऐसे प्रतिबंध पुट्टास्वामी केस 2017 में उल्लेखित तीन शर्तों को पूरा करते हैं

पुट्टास्वामी केस-2017 निजता का अधिकार (अनुच्छेद-21), को सरकार द्वारा तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है, जब वह तीन टेस्ट/शर्तों पर खरी उतरती हो -

1) **कानून** : सरकार की कार्रवाई किसी कानून पर आधारित होनी चाहिए
2) **जरुरत** : कोई वैध उद्देश्य होना चाहिए
3) **आनुपातिकता** : कार्रवाई उद्देश्य के अनुपात में होनी चाहिए

THE HINDU

UNFPA's population report turns spotlight on bodily autonomy

State of World Population 2021 report

The report, 'My Body is My Own', shows only 55% of women are fully empowered to make choices.

April 15, 2021 10:31 pm | Updated 10:32 pm IST - NEW DELHI

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) (1969, न्यूयॉर्क) (विशिष्ट एजेंसी नहीं)

- यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है
- पुराना नाम - जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष

Bodily Autonomy (शारीरिक स्वायत्तता) के उल्लंघन का उदाहरण

बाल विवाह, महिला जननांग कर्तन
LGBTQ+ के खिलाफ भेदभाव और हिंसा
घर या भोजन के लिए अवांछित सेक्स
गर्भनिरोधक की कमी के कारण हुई अनचाही गर्भावस्था

Sealed Cover Jurisprudence

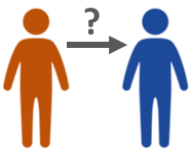

THE HINDU

Explained | What is sealed cover jurisprudence and why is it being opposed?

Questioning the Kerala HC's decision to uphold the MIB's revocation of Malayalam news channel MediaOne's broadcasting license, 11 MPs and others criticised 'sealed cover jurisprudence'

February 18, 2022 01:43 pm | Updated March 16, 2022 02:39 pm IST

समस्या

- ओपन कोर्ट के सिद्धांत के खिलाफ है
- नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांत के खिलाफ है

आप पर आरोप है कि #######
आपको जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि ######

***Sealed Cover Jurisprudence* (सीलबंद कवर न्यायशास्त्र)**

- ❑ न्यायालय (SC/HC/निचली अदालत) सीलबंद लिफाफे में जानकारी स्वीकार करता है, जिसे केवल न्यायाधीशों द्वारा ही देखा जा सकता है ।
- ❑ यह किसी कानून में परिभाषित नहीं है

इसका उपयोग निम्न मामलों में किया जा सकता है

- ➢ राष्ट्रीय सुरक्षा, आधिकारिक गोपनीयता, आदि
- ➢ जांच में रुकावट को रोकने के लिए
- ➢ बलात्कार पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए

Supreme Court Rules 2013 - आर्डर XIII (मई 2014 में नोटिफाइड)

- ➢ CJI / न्यायालय, किसी दस्तावेज़ को सीलबंद लिफाफे में गोपनीय रखने का निर्देश दे सकते हैं, यदि वह जनहित में नहीं है

Evidence Act, 1872 - धारा 123

- ➢ एक पब्लिक ऑफिसर को अप्रकाशित आधिकारिक दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है
- ➢ बिना सरकार की अनुमति के, कोई भी, अप्रकाशित आधिकारिक अभिलेखों से मिली जानकारी को साक्ष्य के रूप में नहीं दे सकता है

Redaction (सीलबंद लिफाफे का विकल्प)

- राफेल डील रिपोर्ट में CAG ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया
- इसका अर्थ है - प्रकाशन से पहले किसी दस्तावेज़ से संवेदनशील जानकारी को हटाना
- इसका उपयोग अन्य देशों के सर्वोच्च लेखापरीक्षा (Audit) संस्थानों की Audit रिपोर्ट में नहीं किया जाता है

Bail

THE HINDU

Right to seek bail implicit in Constitution: Supreme Court

Against Rajasthan judge's order of blanket ban on bails and appeals

October 01, 2021 12:03 am | Updated 12:32 am IST – NEW DELHI

"The right of an accused, an undertrial prisoner or a convicted person awaiting appeal court's verdict to seek bail on suspension of sentence is recognised in Sections 439, 438 and 389 of the Code of Criminal Procedure," a judgment by a Bench of Justices L. Nageswara Rao and Aniruddha Bose said.

कैद (Detention) किये जाने का उद्देश्य -

- आरोपी को सजा देने के लिए ? **नहीं**
- जांच और मुकदमे के लिए आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ? **हाँ**
- बालचंद बलिया v/s राजस्थान केस, 1978 में SC ने कहा था:- "जमानत नियम है और जेल अपवाद है" 'Bail is rule, jail is exception'

जमानत v/s पैरोल

- जमानत, अभियुक्त को ट्रायल से पहले / ट्रायल के दौरान दी जाती है ।
- पैरोल, सजा काट रहे अपराधी को दी जाती है । (क्लास-6 पेज-60)

- CrPC "जमानत" को परिभाषित नहीं करता है
- CrPC की विभिन्न धाराएं "जमानत" से संबंधित हैं
- CrPC "जमानती" और "गैर-जमानती" अपराध को परिभाषित करता है

जमानती v/s गैर जमानती अपराध

- जमानती अपराध → जमानत एक अधिकार है
- गैर-जमानती अपराध → जमानत अधिकार नहीं है

- दोष साबित होने और सजा मिलने के बाद भी जमानत मिल सकती है? **हां** (यदि फैसले के खिलाफ अपील की हो)
- जमानत, सिर्फ जज ही नहीं, पुलिस अफसर भी दे सकते हैं ? **हाँ**
- जमानत के लिए शर्तें अत्यधिक कठोर नहीं होनी चाहिए

वैधानिक जमानत (Statutory Bail)

- यह एक अधिकार है, जो कि अपराध की प्रकृति पर आधारित नहीं होता है
- यह तब दी जाती है जब पुलिस निर्दिष्ट समय में जांच पूरी न कर पाए

नियमित जमानत (Regular Bail)	अग्रिम जमानत (Interim Bail)
गिरफ्तारी के बाद, यानी जब व्यक्ति हिरासत में होता है	जब किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसे गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है
किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाती है	सत्र न्यायालय या HC द्वारा दी जाती है

अग्रिम जमानत
(CrPC Section 438)
स्वतंत्रता (Liberty) की रक्षा (अनुच्छेद-21) के लिए, 1973 में 41वें विधि-आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया था।

अंतरिम जमानत अग्रिम जमानत या नियमित जमानत की सुनवाई से पहले

ट्रांजिट जमानत / ट्रांजिट अग्रिम जमानत

- CrPC में इसका अलग से उल्लेख नहीं है।
- इसमें व्यक्ति को समय मिल जाता है ताकि वह उस राज्य में जमानत के लिए apply कर सके, जहां मामला दर्ज है।
- यह उस व्यक्ति को मिलती है जिसे किसी अन्य राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका हो ।

उदाहरण

- राज्य "A" में मामला दर्ज है। आपको "A" की अदालत से जमानत मिलेगी
- लेकिन अभी आप राज्य "B" में हैं। जमानत के लिए आप "A" जाओगे, पर उससे पहले ही "A" की पुलिस, "B" में आके, आपको पकड़ सकती है।
- ऐसी गिरफ्तारी से बचने के लिए, आप "B" में अदालत से जमानत माँगोगे, ताकि आप "A" में जाके जमानत के लिए आवेदन कर पाओ

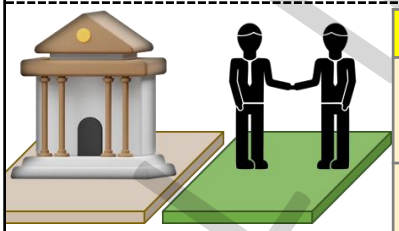

कंपाउंडेबल अपराध	नॉन-कंपाउंडेबल अपराध
समझौते की अनुमति है (दोनों पक्ष आपस में मामले को सुलझा सकते है)	समझौता करने की अनुमति नहीं है (चूँकि इन अपराधों से समाज भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है)
मानहानि, चोरी, जानबूझ कर चोट पहुँचाना, आदि	रैश ड्राइविंग, हत्या, बलात्कार, आदि।

मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं कि एक गंभीर/संगीन अपराध किया गया है

संज्ञेय अपराध	असंज्ञेय अपराध
पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है	पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट चाहिए
अपहरण, हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, आदि	हमला, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि आदि

Extra Info- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC-ST Act 1989)

- इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं (cognizable and non-bailable)
- **इस अधिनियम की धारा 18 के तहत**
  - CrPC की धारा 438 लागू नहीं होगी.
  - यानी SC-ST Act 1989 के तहत आने वाले अपराधों के लिए **अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं है**
- **सुप्रीम कोर्ट ने पृथ्वी राज चौहान केस 2020 में कहा था**
  - यदि शिकायतकर्ता यह न दिखा पाए की मामला SC-ST Act का है, तो धारा 18 लागू नहीं होगी
- **इसलिए, अग्रिम जमानत के लिए**
  - विशेष अदालत जा सकते है और उसके आदेश के खिलाफ HC में अपील भी कर सकते है

Narco test

FREE PRESS JOURNAL

Ankita Bhandari murder: All accused refuse to undergo narco test; Court lists matter for January 3

Agencies | **Updated:** Friday, December 23, 2022, 01:47 PM IST

Sodium Pentothal / Sodium Thiopental / Truth Serum

- यह एक सामान्य एनेस्थेटिक है , जो बहुत जल्दी काम करता है लेकिन केवल थोड़े समय के लिए ही
- इसका उपयोग सर्जरी से पहले मरीजों को बेहोश करने के लिए किया जाता है
- ये Barbiturate class की दवाइ है:-
  - केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous system) पर depressants के रूप में कार्य करती हैं
  - प्रभाव: बेहोशी, नींद, एनेस्थीसिया, आदि

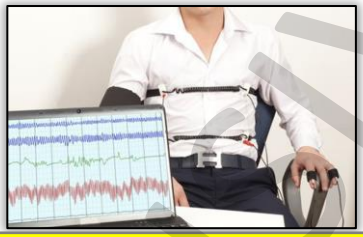

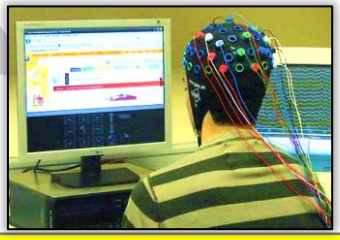

नार्को टेस्ट	पॉलीग्राफ टेस्ट	ब्रेन मैपिंग टेस्ट
❖ Sodium Pentothal इंजेक्शन दिया जाता है	❖ कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। ❖ उपकरणो (कार्डियोकफ, इलेक्ट्रोड आदि) द्वारा नब्ज़, रक्तचाप, पसीना आदि को मापा जाता हैं।	❖ कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। ❖ मस्तिष्क के विद्युत व्यवहार (Electrical Behaviour) का अध्ययन करने के लिए Electroencephalogram का उपयोग किया जाता है
❖ व्यक्ति बेहोश/सम्मोहित/अर्धचेतन हो जाता है। ❖ व्यक्ति झूठ बोलने में अक्षम हो जाता है।	❖ व्यक्ति पूरी तरह सतर्क/सजग/चेतन रहता है। ❖ वह झूठ बोलने में सक्षम रहता है।	❖ व्यक्ति पूरी तरह सतर्क/सजग/चेतन रहता है। ❖ वह झूठ बोलने में सक्षम रहता है।
❖ यह माना जाता है कि वह व्यक्ति केवल सच ही बोलेगा	❖ शारीरिक प्रतिक्रियाओं (दिल की धड़कन, पसीना आदि) में बदलाव से झूठ का पता लगाया जा सकता है।	❖ अपराध से संबंधित छवियों या शब्दों के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके झूठ पता लगाया जा सकता है।

- ऐसे परीक्षणों की सटीकता संदिग्ध है। इनमें ब्रेन मैपिंग सबसे बेहतर मानी जाती है।
- ये परीक्षण अदालत में स्वीकारोक्ति (Confession) या साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं।
- लेकिन, ये पुलिस को मामले की अहम जानकारी दे सकते हैं ।
- ऐसे परीक्षणों के लिए अभियुक्त की सहमति आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी v/s कर्नाटक Case, 2010 में कहा था :

- अभियुक्त की स्पष्ट सहमति के बिना नार्को-एनालिसिस, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग अवैध हैं ।
- जब तक कोई व्यक्ति स्वेच्छा से सहमति नहीं देता, तब तक ये तरीके आत्म-अभिशंसन (Self-Incrimination) के विरुद्ध अधिकार [अनुच्छेद 20(3)] और निजता का अधिकार [अनुच्छेद 21] का उल्लंघन करते हैं

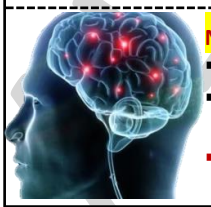

Note:

- ब्रेन मैपिंग टेस्ट को 'ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट' और 'P-300 टेस्ट' भी कहते है
- मस्तिष्क कोशिकाएं, विद्युत आवेगों (Electric Impulses) द्वारा communicate करती हैं और हर समय सक्रिय रहती हैं, यहां तक कि नींद के दौरान भी ।
- Electroencephalogram (EEG), खोपड़ी से जुड़ी Small Metal Discs (Electrodes) का उपयोग करके, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापता है।

CPIA 2022

Criminal Procedure Identification Act, 2022

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022

- यह कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की जगह लेता है
- यह पुलिस और जेल अधिकारियों को गिरफ्तार किये गए लोगों के कुछ निश्चित माप (Measurements) लेने की अनुमति देता है
- व्यक्ति माप देने से इंकार नहीं कर सकता है

DATA

- डाटा, NCRB द्वारा मेन्टेन किया जाएगा
- डाटा, 75 साल के लिए स्टोर रहेगा
- यदि व्यक्ति निर्दोष साबित हुआ, तो डाटा नष्ट कर दिया जाएगा

Note:

- 1920 के कानून ने फोटो, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट एकत्र करने की अनुमति दी थी
- CPIA 2022 ने इसका दायरा बढ़ाया और आइरिस, रेटिना, सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, ब्लड, हेयर आदि एकत्र करने की अनुमति भी दी है

NAFIS

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Explained: What is NAFIS — and the story of how fingerprinting began in India

Written by Raghu Malhotra Follow

New Delhi | August 21, 2022 09:56 IST NewsGuard

According to the Ministry of Home Affairs, NAFIS, which was developed by the National Crime Records Bureau (NCRB), would help in the quick and easy disposal of cases with the help of a centralised fingerprint database.

1897

विश्व का पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो 1897 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था

सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो

- 1955 में कलकत्ता में स्थापित
- अब दिल्ली में है और NCRB के अंतर्गत आता है

Prelims 2014

फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के अलावा, किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है?

1. आइरिस स्कैनिंग 2. रेटिनल स्कैनिंग 3. आवाज की पहचान

सही उत्तर का चयन करें

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं

- प्रत्येक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स यूनिक (अद्वितीय) होते हैं
- इनके बनने में, आनुवंशिक (genetic) और पर्यावरणीय (environmental), दोनों कारको की भूमिका होती है
- यहां तक कि, एक जैसे DNA वाले जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट्स भी अलग-अलग होते हैं।
- यूरोप में फिंगरप्रिंट्स की विशिष्टता, पहली बार 1788 में, जर्मन एनाटोमिस्ट जोहान मेयर द्वारा प्रस्थापित की गई थी

Fingerprint Analysis & Criminal Tracing System (FACTS)

- 1992 में लॉन्च किया गया था (राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने मैनुअल रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की सिफारिश की थी)
- यह भारत की पहली स्वचालित (automated) फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली थी
- इसे अपग्रेड किया जाता रहा और अब इसकी जगह NAFIS ने ले ली है

राष्ट्रीय स्वचालित फ़िंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) ***National Automated Fingerprint Identification System***

- NCRB द्वारा विकसित, यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अपराध संबंधी फिंगरप्रिंट्स का एक डेटाबेस है
- CCTNS (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) से कनेक्टेड है
- कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ (Law Enforcement Agency) रियल टाइम में फिंगरप्रिंट अपलोड करके मिलान कर सकती हैं
- यह अपराध के लिए गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति को 10 अंको वाला एक यूनिक राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट संख्या (NFN) देता है
- NFN व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान और अलग-अलग FIR में same रहेगा
- NFN के पहले दो अंक राज्य कोड होते हैं, जिसके बाद एक sequence नंबर होता है

परीक्षा में विकल्पों को ध्यान से पढ़ें

मध्यप्रदेश पहला राज्य है जिसने फिंगरप्रिंट्स का उपयोग करके मृत व्यक्ति की पहचान की? **नहीं**

मध्यप्रदेश पहला राज्य है जिसने NAFIS का उपयोग करके मृत व्यक्ति की पहचान की? **हाँ**

Cri-MAC (क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर)

- MHA द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया, NCRB द्वारा प्रबंधित
- राज्यों के बीच रियल टाइम में अपराध संबंधी जानकारी साझा करने के लिए